साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 24-30 जून 2024 वर्ष-10, अंक-10

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

- मोदी कैबिनेटः 14 खरीफ फसलों की एमएसपी पर लगी मुहर

केंद्र ने खोला खजाना! धान का नया एमएसपी 2,300 क्विंटल

» किसानों को एमएसपी के तौर पर करीब दो लाख करोड़ मिलेंगे

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अनुमोदन दिया है। 2018 के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि किसानों को लागत मूल्य का कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी के रूप में दिया जाएगा। सीएसीपी ने इसी आधार पर अपनी सिफारिशें की हैं। दस फसलों की एमएसपी उनके औसत उत्पादन लागत से डेढ़ गुना है और 4 फसलों की उससे भी अधिक है। धान की एमएसपी 2300 प्रति क्विंटल की गई है, जो पिछले सीजन की तुलना में 117 रुपए अधिक है। खरीफ सीजन की फसलों के लिए एमएसपी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार के फैसले से किसानों को एमएसपी के रूप में दो लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पिछले सीजन से 35,000 करोड़ अधिक है। पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई फैसलों के माध्यम से बदलाव के साथ निरंतरता पर केंद्रित है। मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ की फसलों पर एमएसपी को मंजूरी दी है।

दो लाख नए गोदाम बनाएगी सरकार

वैष्णव ने कहा कि एमएसपी पर धान और अन्य मोटे अनाजों की सरकारी खरीद एफसीआई और राज्यों की एजेंसियों द्वारा की जाएगी। दलहन और तिलहन की खरीद नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के द्वारा की जाएगी। कपास की खरीद कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा की जाएगी। खरीद में अगर एजेंसियों को कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। सरकार की ओर से दो लाख नए गोदाम बनाने का काम किया जा रहा है।

फसल	एमएसपी	बढ़ी	फसल	एमएसपी	बढ़ी
धान	2,300	117	अरहर	7550	550
कपास	7,521	501	उड़द	7400	450
बाजरा	3375	125	मूंगफली	6783	406
ज्वार	3375	196	रामतिल	8717	983
रागी	4290	444	सूरजमुखी	7230	520
मक्का	2225	135	तिल	9267	632
मूंग	8682	124	सोयाबीन	4892	292

सीएम मोहन यादव ने कहा

अन्नदाताओं को दी पहली गारंटी पूरी

इधर, मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एमएसपी में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार माना और किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए सभी आवश्यक खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी देने से किसानों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी और उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। पीएम की यह पहल जनकल्याण की भावना से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली सिद्ध होगी। एमएसपी में इस वृद्धि से पीएम की अन्नदाताओं को दी गई पहली गारंटी पूरी होगी और देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। समर्थन मूल्य पर की गई यह वृद्धि सिद्ध करती है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।

गुजरात अव्वल, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र

पपीता उत्पादन में तीसरे पायदान पर मध्य प्रदेश

भोपाल। जागत गांव हमार

फलों में पपीते का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पपीते का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी कहां से पूरे देश में सबसे अधिक आता है पपीता। इसके लिए पढ़ें ये रिपोर्ट-भारत में सबसे अधिक पपीते का उत्पादन गुजरात में होता है। आंध्र प्रदेश को छोड़कर गुजरात पपीता उत्पादन के मामले में सबसे आगे निकल गया है। यहां के किसान हर साल बंपर पपीते की पैदावार करते हैं। देश की कुल पपीता उत्पादन में गुजरात का 20.69 फीसदी की हिस्सेदारी है। इस फल का उपयोग पकाकर और कच्चा दोनों तरीके से किया जाता है। वहीं पपीता का उत्पादन गुजरात के बाद बड़े पैमाने पर आंध्र प्रदेश में होता है। यहां के किसान 16.72 फीसदी पपीते का उत्पादन करते हैं। पपीते में भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार पाया जाता है। इसलिए लोग इसे बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं।

पपीता अपच के लिए रामबाण इलाज

वहीं पपीता उत्पादन में तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। यहां पपीते की 9.92 फीसदी पैदावार की जाती है। इसमें विटामिन-ए पाया जाता है। यह कई बीमारियों में लाभदायक माना जाता है। बात करें उत्पादन की तो चौथे पायदान पर महाराष्ट्र है। यहां के किसान 9.39 फीसदी पपीते का उत्पादन करते हैं। पपीता अपच की समस्याओं वाले लोगों के लिए रामबाण इलाज माना जाता है। वहीं पपीता उत्पादन में पांचवें स्थान कर्नाटक का है। यहां पपीते की 8.52 फीसदी पैदावार की जाती है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार (2023-24) आंकड़ों के अनुसार पपीते के पैदावार में छठे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। यहां हर साल किसान 6.90 फीसदी पपीते का उत्पादन करते हैं। वहीं ये छह राज्य मिलकर लगभग 75 फीसदी उत्पादन करते हैं।

देश के उत्पादन में हमारी 24.09 फीसदी हिस्सेदारी, पांच राज्य मिलकर 85 प्रतिशत कर रहे चना उत्पादन

मध्य प्रदेश चना दाल उत्पादन में अव्वल

भोपाल। जागत गांव हमार

भारतीय भोजन दाल के बिना अधूरा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चने की दाल का भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। यानी कहां से पूरे देश में सबसे अधिक पहुंचता है चने का दाल। इसके लिए पढ़ें **जागत गांव हमार** की खास रिपोर्ट...दाल शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जिसे खाने से कई बीमारियों में फायदा मिलता है। वहीं, चने के दाल से कई अलग-अलग प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक चने की दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। यानी चना दाल उत्पादन के मामले में ये राज्य अव्वल है। यहां के किसान हर साल बंपर चना का उत्पादन करते हैं। देश की कुल चना दाल उत्पादन में यहां का 24.09 फीसदी की हिस्सेदारी है।

मसूर, उड़द, मूंग जैसी साधारण दाल के अलावा चने जैसी टेस्टी दालें आपके घर में अक्सर पकाई जाती हैं। वहीं उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। देश के कुल चना दाल उत्पादन में इस राज्य की हिस्सेदारी 23.01 फीसदी है। चने की खेती रबी सीजन में की जाती है। साथ ही यह एक व्यावसायिक फसल है।

राजस्थान तीसरे और यूपी 5वें नंबर पर

वहीं उत्पादन के मामले में भारत के टॉप तीन राज्यों में तीसरा नंबर राजस्थान का है। यहां चने की दाल का 17.08 फीसदी उत्पादन होता है। दाल का सेवन हर भारतीय घरों में बड़े ही चाव से किया जाता है। दाल-चावल या दाल-भात न खाएं, तो जैसे उनका भोजन अधूरा लगता है। अब जान लीजिए कि गुजरात चना दाल के उत्पादन में चौथे नंबर पर है। इस राज्य के किसान हर साल 12.02 फीसदी चना दाल का उत्पादन करते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के (2022-23) आंकड़ों के अनुसार चना दाल के पैदावार में पांचवें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यहां के किसान हर साल 6.02 फीसदी चना दाल का उत्पादन करते हैं। वहीं ये पांच राज्य मिलकर 85 फीसदी चना दाल का उत्पादन करते हैं।

सरकार का लक्ष्य-ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने और डिजिटल समावेशन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने शिवपुरी गुना और अशोकनगर को दी सौगात

मध्यप्रदेश के तीन गांव बनेंगे '5-जी इंटेलिजेंट विलेज'

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में बड़ी जीत के बाद गुना। दूरसंचार मंत्रालय का पदभार 10 जून से संभाला है। एक सप्ताह बाद ही दूर संचार मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण इलाकों की एक नई पहल में शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले के तीन गांव को लाभान्वित किया।

दूरसंचार मंत्रालय ने 5-जी इंटेलिजेंट विलेज और क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम श्रेणियों के तहत प्रस्ताव की घोषणा की है। इस '5-जी इंटेलिजेंट विलेज' के उद्देश्य के तहत ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने और डिजिटल समावेशन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5-जी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।

देश के इन गांवों को मिलेगी 5जी

दूरसंचार मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5जी इंटेलिजेंट विलेज योजना को देश के कई राज्यों के दूरस्त गांवों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। यह नवसौगात देश के इन राज्यों के इन गांवों को दी जाएगी। इसमें धमज्ज, जिला- आनंद, गुजरात, रामगढ़ उर्फ राजाही, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, आनंदपुर जलबेरा, जिला- अंबाला, हरियाणा, बाजारगांव, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र, भगवानपुरा, जिला- भीलवाड़ा, राजस्थान, डबलोंग, जिला- नागांव, असम, रावसर, जिला- अशोकनगर, मध्य प्रदेश, आरी, जिला- गुना, मध्य प्रदेश, बांसखेड़ी, जिला- शिवपुरी, मध्य प्रदेश और बुरीपजलेम, जिला- गुंटूर, आंध्र प्रदेश को दी जाएगी।

दी जाएगी ये सुविधाएं

इन चयनित गांवों को 5जी के अल्ट्रा-रिलायबल लो-लेटेंसी कम्युनिकेशन (यूआरएलएलसी) और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन (एमएमटीसी) तकनीकों का प्रभावी तौर पर उपयोग में समर्थ बनाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं, जो 5जी कनेक्टिविटी के फायदों को प्रदर्शित करते हैं। बता दें की इन प्रस्तावों में भागीदारी के लिए उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और उन सरकारी विभागों को आमंत्रित किया गया है जो दूरसंचार उत्पादों एवं समाधानों के प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास एवं वाणिज्यिकरण जैसे कार्यों में शामिल हैं।

मंत्रालय का ये है लक्ष्य

5जी इंटेलिजेंट विलेज प्रोग्राम का प्रभाव मंत्रालय का लक्ष्य है कि 5प्रतिशत टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रामीण इलाकों में अभूतपूर्व बदलाव लाया जा सके। यह पहल कृषि, शिक्षा, स्वास्थ, शासन और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।

तीन हजार लीटर तक दूध देने की क्षमता

डेयरी के लिए फायदेमंद थारपारकर नस्ल

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत में गायों की कई अलग-अलग नस्लें पाई जाती हैं। गायों का न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि रोजगार की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। गाय के दूध के अलावा दही, घी, गोबर और गौमूत्र की भी बाजार में काफी मांग है। ऐसे में गौपालन एक उन्नत व्यवसाय है। इसे बड़े और छोटे दोनों स्तर पर किया जा सकता है। गौपालन के जरिए किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके जरिए किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज है गौपालन से जुड़ी जानकारी। कई बार किसानों के पास जानकारी का अभाव होता है। जिसके चलते उन्हें रोजगार शुरू करने या उस रोजगार को आगे बढ़ाने में परेशानी होती है। अगर आप भी गाय पालन कर आय कमाना चाहते हैं तो गाय की सही नस्ल का चुनाव करना बहुत जरूरी है।

गाय की कीमत- गाय के सही नस्ल की बात करें तो डेयरी उधयोग के लिए गाय की थारपारकर नस्ल बेहद फायदेमंद है। राजस्थान थारपारकर नस्ल की गायों का जन्मस्थान है। जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जहां थारपारकर गायों की संख्या अधिक है। थारपारकर गायों का मुंह लंबा होता है। सींग मध्यम आकार के होते हैं। ये गायें सबसे गर्म स्थानों पर भी आसानी से रहने की क्षमता रखती हैं। एक थारपारकर गाय की कीमत 15-20 हजार से लेकर 40-45 हजार तक है। यह गाय 8 लीटर से 10-12 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है।

थारपारकर गाय की विशेषता

थारपारकर गायें अपनी दोहरी क्षमता के लिए जानी जाती हैं। ये न सिर्फ दूध के मामले में अच्छी हैं, बल्कि खेती में भी उपयोगी हैं। इसके अलावा, अगर थारपारकर गाय को हरा चारा कम मिले, तो भी इसकी दूध उत्पादकता में कमी नहीं आती। इस नस्ल की गाय एक ब्यांत में 1400 से 1600 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। थारपारकर गायों का इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है, जिसकी वजह से ये बीमार नहीं पड़तीं और अगर बीमार पड़ भी जाती हैं, तो जल्दी ठीक हो जाती हैं।

इस तरह बढ़ाएं गाय का दूध

थारपारकर गाय का दूध बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले गाय के कम दूध देने का कारण जानना जरूरी है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से गाय की दूध उत्पादकता कम हो सकती है और इन समस्याओं को ठीक करके पशु का दूध बढ़ाया जा सकता है। अगर गाय के रहने की जगह तंग है या उसके रहने की जगह में हवा का संचार ठीक से नहीं हो रहा है या फिर पशुशाला बहुत गर्म है तो गाय का दूध कम हो सकता है। ऐसी स्थिति में गाय का दूध बढ़ाने के लिए उसके रहने की जगह को खुला, हवादार और छायादार बनाएं।

कैल्शियम की कमी से घट जाता है दूध

गाय को अगर जूं और टिक्स की समस्या है तो उनकी दूध उत्पादकता भी कम हो जाती है। अगर पशु के शरीर पर जूं और टिक्स की समस्या है तो ये परजीवी उसका खून चूसते रहते हैं। जिससे पशु तनाव में आ जाता है और उसकी दूध उत्पादकता कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में पशु के शरीर को नीम के पानी से साफ करना चाहिए। इससे पशु को जूं और टिक्स से छुटकारा मिलेगा और उनकी दूध उत्पादकता भी बढ़ेगी। कैल्शियम की कमी से थारपारकर गाय का दूध उत्पादन भी कम हो सकता है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए आप गाय को कैल्शियम जेल नामक सप्लीमेंट दे सकते हैं, इससे गाय का दूध उत्पादन बढ़ जाएगा।

उत्पादन पर पड़ेगा असर, चौंकाने वाली रिसर्च

खेतों में लगातार गहरी जुताई से भी नुकसान

खरगोन। जागत गांव हमार

अधिक उत्पादन के लिए किसान भाई अगर अपने खेतों में लगातार गहरी जुटाई करते हैं, तो आने वाले समय में इससे उन्हें भारी नुकसान उठना पड़ सकता है। जी हां, अनुसंधान ने पाया है की खेतों में लगाकर गहरी जुटाई करने से जमीन में मिट्टी की संरचना बिगड़ती है। साथ ही मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी आ जाती है। जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। खरगोन कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. जीएस कुलमी ने बताया है कि खेतों में गहरी जुताई के फायदे भी है और नुकसान भी है। फायदों की बात की जाएं तो मिट्टी की गहरी जुताई करने से सूर्य की सीधी रोशनी मिट्टी में पड़ने से वायु संचार बढ़ता है। और मिट्टी में मौजूद कीड़े मर जाते हैं। खरपतवार भी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर वर्षा ऋतु में सुखा पड़ जाता है तो भी खेतों में नमी बनी रहती है। लेकिन, लगातार गहरी जुताई करने से खेतों को भारी नुकसान पहुंचता है।

गहरी जुताई के नुकसान

कृषि वैज्ञानिक डॉ. कुलमी ने कहा की अभी अनुसंधान से पता चला है कि वैज्ञानिक द्वारा गहरी जुताई से किसानों को परहेज रखने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि, लगातार गहरी जुताई करने से मिट्टी की संरचना बिगड़ती है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। उन्होंने बताया की गहरी जुताई करने से जमीन खुल जाती है। जिससे जमीन के अंदर का ऑर्गेनिक कार्बन धूप में उड़ने लगता है और जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी हो जाती है। पता चला है कि लगातार गहरी जुताई करने से आने वाले समय में उत्पादन में कुछ कमी आती है। इसलिए किसान भाईयों को हर साल गहरी जुताई नहीं करना चाहिए। गहरी जुताई को तीसरे या चौथे साल में ही करना चाहिए। जिससे गहरी जुताई का दुष्प्रभाव भी सामने नहीं आएगा और फायदा भी मिलेगा।

इस विधि से किसानों को होगा डबल मुनाफा

सतना में एक ही समय में धान की खेती के साथ मछली पालन

सतना। आज का युग परंपरागत खेती के साथ ही स्मार्ट फार्मिंग का है। इससे किसान न सिर्फ़ एक साथ एक ही खेत में दो तरह की फसल ले सकते हैं, बल्कि आय को भी डबल कर सकते हैं। एक ऐसी ही तकनीक सतना के किसान भी अपना रहे हैं। इसे एक्वा कल्चर फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। एक्वा कल्चर फार्मिंग को जलीय खेती कहते हैं। इस खेती में किसान धान की फसल के साथ-साथ मछली पालन भी कर सकता है। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश सिंह ने बताया कि एक्वा कल्चर फार्मिंग यानी जलीय खेती किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे किसान बड़ी ही आसानी से अपना मुनाफा दोगुना कर सकते हैं। जलीय खेती यानी जलीय जीवों जैसे मछली, क्रस्टेशियंस, मोलस्क, शैवाल और जलीय पौधों की खेती। एक्वा कल्चर में एक निश्चित क्षेत्र में एक ही जगह 2 फसलों की खेती ली जा सकती है। मछली पालन भी एक प्रकार का एक्वा कल्चर है। किसान धान की फसल संग मछली पालन कर सकते हैं।

कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि सामान्यत: वर्षा ऋतु में धान की खेती की जाती है, जिसमें हम जलीय खेती यानी मछली पालन कर सकते हैं। इसके लिए खेतों में व्यवस्थित मेड़ बंदी होनी चाहिए, जहां पानी हमेशा भरा ही रहे। इसके बाद धान की उन किस्मों का चयन करना होगा जो लंबे समय में पकने वाली यानी 140 से 145 दिन बाद पकने वाली हों। क्योंकि मछलियों की अच्छी ग्रोथ के लिए इतना समय उपयुक्त होता है। वहीं खेत में मेड़ बंदी कर पानी की ऐसी व्यवस्था करें ताकि 7-8 इंच पानी खेत में बना रहे, ताकि मछलियों को समस्या न हो।

किस किस्म की मछली पालें

धान के साथ एक्वा कल्चर में मछली की कुछ चुनिंदा किस्में ही पाली जाती हैं। सतना सहित विंध्य क्षेत्र के वातावरण के अनुसार कॉमन कॉर्प किस्म की मछली उत्तम है। यह 4 से 5 महीने में बढ़िया ग्रोथ करती है और वजन में 500 से 750 ग्राम तक की तैयार भी हो जाती है। इस प्रकार जलीय खेती कर किसान एक ही खेत में दो अलग-अलग फसल ले सकते हैं। अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं।

-तकनीकी देखभाल में किसानों की बनेगी मददगार

अब एआई आवारा पशुओं से बचाएगी फसल

भोपाल। जागत गांव हमार

अब एआई का जमाना है। ऐसे में खेती और किसान भी इस अत्याधुनिक तकनीक से अछूते नहीं रहेंगे। एआई आधारित मोबाइल ऐप किसानों के लिए कई मायनों में मददगार साबित होगा। इसकी मदद से किसानों को मौसम जनित मुसीबतों के अलावा खेत में हमले की भी जानकारी मिल जाएगी। यूपी और एमपी सहित देश के तमाम इलाकों में छुट्टा पशु किसानों की फसलें नष्ट कर देते हैं। किसानों की आय पर बुरी तरह से असर डाल रही इस समस्या से बुंदेलखंड जैसे इलाकों में, जहां किसान पहले से ही बदहाली के शिकार हैं, खेती का संकट बेहद गंभीर हो गया है। किसानों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने में एआई की मदद ली गई है। झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा एआई आधारित एक मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। जल्द ही इसकी शुरुआत बुंदेलखंड से होनी है, इसलिए इस इलाके में खेती का डाटा जुटाने का काम अंतिम चरण में है। इसकी मदद से न केवल छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा की जा सकेगी, बल्कि किसानों को मौसम जनित मुसीबतों और फसलों पर कीटों के प्रकोप से बचने के उपायों का भी पता चल जाएगा। यह ऐप देश के किसानों को खेती में कीट प्रबंधन कराने में मदद करने के साथ ओलावृष्टि, अत्यधिक बारिश, पाला पड़ने और सूखे की मार से फसलों को बचाने के अलर्ट भी देगा।

मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट

किसानों के लिए फसल को कीट पतंगों और मवेशियों के प्रकोप से बचाने में जो पैसा लगता है, उससे कृषि की लागत बहुत बढ़ जाती है। यह स्थिति किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। अब इस समस्या से निपटने के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विवि के वैज्ञानिकों ने एआई को किसानों का मददगार बनाया है। इसके लिए एआई बेस्ड मोबाइल एप विकसित किया गया है। विश्वविद्यालय के एग्रोफारेस्टरी विभाग के प्रमुख डॉ. प्रभात जांभुलकर ने बताया कि इस ऐप को रियल टाइम डाटा से लैस किया जा रहा है।

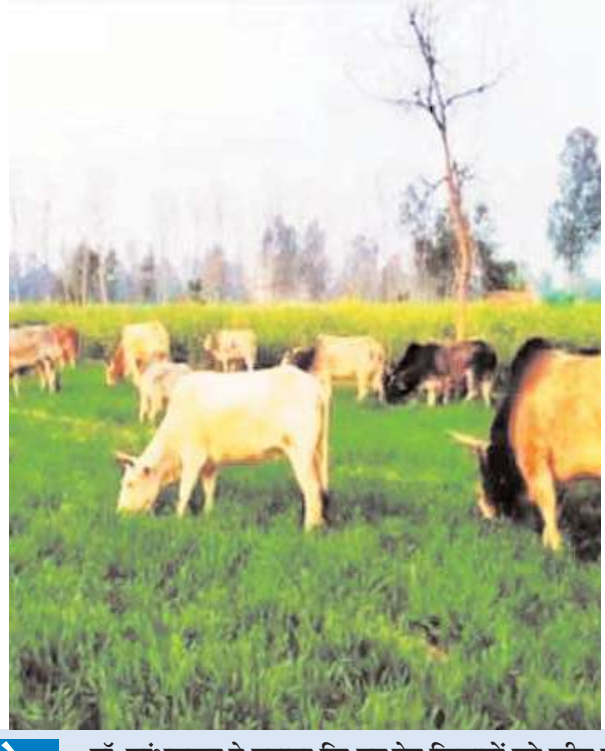

अगले साल से मिलेगी सेवा

डॉ. जांभुलकर ने बताया कि इस साल ऐप का ट्रायल पूरा होने के बाद अगले साल से यह ऐप किसानों की सेवा में हाजिर होगा। उन्होंने बताया कि यह मल्टीटास्किंग ऐप है। इसकी मदद से किसानों को फसल पर कीट पतंगों का प्रकोप होने से पहले ही मोबाइल फोन पर अलर्ट मिल जाएगा। एआई तकनीक से पहले ही पता चल जाएगा कि कब किस इलाके में मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए किस फसल पर कौन से कीट का प्रकोप होने वाला है। इतना ही नहीं इस ऐप की मदद से मवेशियों और टिड्डी दल के प्रकोप का भी अलर्ट किसानों को मिल जाएगा।

समस्याओं का होगा समाधान

गौरतलब है कि मौजूदा स्थिति में किसानों को मौसम, मवेशी और कीट पतंगों के प्रकोप से बचने में काफी ऊर्जा, समय और धन लगाना पड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एआई तकनीक किसानों की समस्याओं के समाधान में कारगर मदद कर सकती है। कृषि क्षेत्र में इसकी संभावनाओं को देखते हुए देश के तमाम अग्रणी संस्थानों में खेती से जुड़े एआई आधारित मोबाइल ऐप विकसित किए जा रहे हैं।

उपाय भी बताएगा ऐप

डॉ. जांभुलकर ने बताया कि यह ऐप किसानों को कीट प्रबंधन और आसन्न प्राकृतिक आपदा से निपटने के उपाय भी सुझा देगा। खेतों में फसल सुरक्षा से जुड़े हालात की हजारों तस्वीरों के माध्यम से रियल टाइम डाटा जुटाया गया है। इसे एआई आधारित ऐप के साथ समायोजित कर इस तकनीक को विकसित किया जा रहा है। इस डेटा पर आधारित ऐप की मदद से किसान अपने खेत में ही मिट्टी की गुणवत्ता की जांच भी कर सकेंगे। मृदा परीक्षण के आधार पर किसानों को यह भी पता चल सकेगा कि उनके खेत में कब किस फसल में कौन से कीट का प्रकोप होगा और इससे बचने के क्या उपाय होंगे।

डब्ल्यूएमओ ने दी चौंकाने वाली जानकारी

सावधान! भारत में खेती को चौपट कर सकता है बढ़ता तापमान

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत के लिए बड़ी चिंता की खबर है। यह खबर वर्ल्ड मेटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएमओ की तरफ से आई है। इसमें बताया गया है कि आने वाले वर्षों में तापमान इस कदर बढ़ेगा कि भारत में खेती की उपज में भारी कमी आ सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले वर्षों में तापमान में ऐसी बढ़ोतरी होगी जो 1991-2020 के मुकाबले अधिक होगी। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2024-2028 के बीच तापमान में बढ़ोतरी 1.1 डिग्री से लेकर 1.9 डिग्री तक पहुंच सकती है। 2024-2028 के बीच एक साल ऐसा भी रह सकता है जिस दौरान तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री तक दर्ज की जा सकती है। इसका असर खेती-बाड़ी पर देखने को मिल सकता है। 2020 से दुनिया में ला-नीना का प्रभाव देखा गया। इसका सबसे बुरा असर एशिया में भारी बारिश और बाढ़ के रूप में देखा गया। खासकर भारत में हालात बहुत खराब रहे। जून 2023 के बाद अल-नीनो का दौर शुरू हो गया जिससे एशिया, खासकर भारत में सूखे की स्थिति पैदा हो गई। अल-नीनो ने स्थिति ऐसी बिगाड़ी कि भारत का एक चौथाई हिस्सा भारी सूखे की चपेट में चला गया।

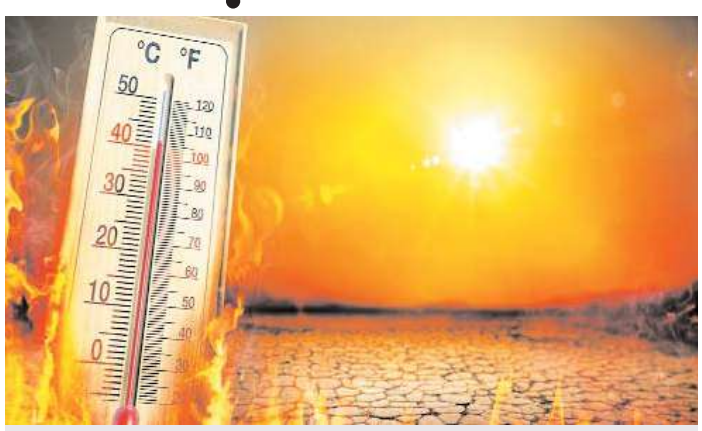

क्लाइमेट चेंज का प्रभाव

क्लाइमेट चेंज से पैदा हुई अल-नीनो की स्थिति ने भारत में खेती-बाड़ी को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। इस दौरान भारत के अधिकांश इलाकों में बेमौसमी बारिश और लू की लहरें देखी गईं। इससे अनाज, दालों और तिलहन का उत्पादन प्रभावित हुआ। डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट बताती है कि उसके पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को बड़ी तैयारी करनी चाहिए। किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे खेती के काम में बदलाव ले आएं। रिपोर्ट बताती है कि 2023-24 में अल-नीनो अपने चरम पर है और इसी साल ला-नीना में तब्दील हो जाएगा।

खेती के लिए लिहाज से ठीक नहीं

डब्ल्यूएमओ की एक रिपोर्ट बताती है कि जून-अगस्त 2024 के दौरान ला-नीना एक्टिव हो सकता है। जुलाई से सितंबर के बीच ला-नीना के एक्टिव होने की संभावना 60 परसेंट है और अगस्त-नवंबर के बीच 70 प्रतिशत एक्टिव होने की संभावना है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि अभी अल-नीनो के दोबारा एक्टिव होने की संभावना न के बराबर है। भारत में ला-नीना अगर प्रचंड रूप लेता है तो इससे खेती बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। ला-नीना से भारी बारिश और बाढ़ की संभावना बनती है जो खेती के लिए लिहाज से ठीक नहीं है।

चौपट होगी खेती-बाड़ी

जलवायु परिवर्तन की बात करें तो इसने भारत सहित पूरी दुनिया को परेशानी में डाल रखा है। अल-नीनो इसी का बाईप्रोडक्ट है। अब गर्मी पहले से अधिक गर्म होती है, इसका असर पहले से अधिक असहनीय होता जा रहा है। साल 2023 में दुनिया के उत्तरी हिस्से में 2,000 साल का सबसे गर्म मौसम रिकॉर्ड किया गया। कनाडा में इतनी गर्मी रही कि जंगलों की आग को बुझाना बेकाबू हो गया। अमेरिका के टेक्सास से लेकर एरिजोना तक इतनी गर्मी रही कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ऐसे में सोचा जा सकता है कि खेती पर इसका कैसा असर रहा होगा और आगे क्या हालात बनेंगे।

किसान जल्द कर सकते हैं आवेदन

मध्यप्रदेश में सिंचाई यंत्रों पर 60 फीसदी तक की सब्सिडी

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के किसानों को अब सिंचाई के लिए समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां पर किसानों को सिंचाई उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। सिंचाई यंत्र सब्सिडी योजना के तहत किसानों को पाइप लाइन सेट, स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम, रैनगन के अलावा अब मिनी स्प्रिंकलर सेट के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इससे संबंधित सूचना कृषि विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आवेदन भरने की शुरूआत 14 जून से हो चुकी है। राज्य के किसानों को वर्ष 2024-25 प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत सिंचाई उपकरण मिनी स्प्रिंकलर सेट दिया जा रहा है। इसके लिए 14 जून 2024 से आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि जून 2014 रखी गई है। जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो 24 जून से पहले पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत जो आवेदन मिलेंगे उनका चयन ऑनलाइन लॉटरी के लिए जरिए किया जाएगा। इसकी जानकारी पोर्टल पर साझा कर दी जाएगी।

मिलेगी भरपूर सब्सिडी

कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही पीएम कृषि सिंचाई योजना के किसानों को सिंचाई उपकरण लेने पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को सब्सिडी का लाभ देने के लिए प्रति जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के सिंचाई यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत सभी वर्गों के लघु और सीमांत किसानों को यूनिट खर्च का 60 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं।

यहां करें आवेदन

मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्र पर अनुदान लेने के लिए किसान पोटर्ल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर जो किसान पहले से रजिसटर्ड हैं वो किसान ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। जबकि नए किसानों को आवेदन करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। किसान अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

हीटवेव से आम पर पड़ रहा बुरा असर, फल की गुणवत्ता में भारी कमी

हीटवेव की वजह से आम पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही आम की कुछ ऐसी किस्में भी है, जो इस भीषण लू में प्राकृतिक रूप से पककर गिर रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि उच्च गुणवत्ता युक्त आम के फलों की भौतिक और जैव रासायनिक विशेषताएं क्या है? इस साल हीटवेव (लू) की वजह से आम के फलों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं, जिससे उनकी वृद्धि, गुणवत्ता और विपणन क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। आम की कुछ किस्में इस समय प्राकृतिक रूप से पककर गिर रहे हैं।

फलों की गुणवत्ता का अध्ययन करने से पता चला है की इस वर्ष हीट वेव (लू) की वजह से फल की क्वालिटी मे भारी कमी देखी जा रही है। पके फलों को काटने के बाद अंदर गुद्दा का जेली में परिवर्तित होने के साथ-साथ फलों में मिठास भी बहुत ही कम मिल रही है। इन परिस्थितियों में यह जानना अति आवश्यक है की उच्च गुणवत्ता युक्त आम के फलों मे क्या-क्या विशेषताएं होनी चाहिए जो उसे विशेष बनाता है।

उच्च गुणवत्ता युक्त आम के फलों में कई तरह की भौतिक और जैव रासायनिक विशेषताएं होनी चाहिए हैं जो उनकी गुणवत्ता, स्वाद और पोषण मूल्य को परिभाषित करते हैं।

आम के फलों की भौतिक विशेषताएं: देखने योग्य होने चाहिए आम के फल

रंग: किस्म के आधार पर, छिलके का रंग हरे से लेकर पीले, नारंगी या लाल तक हो सकता है। एक पका हुआ आम आम तौर पर कम से कम हरे धब्बों के साथ जीवंत, एक समान रंग दिखाता है।

आकार और आकृति: आम की किस्मों के आकार और आकृति में भिन्नता होती है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले फल आम तौर पर बिना किसी विकृति के सुडौल और एक समान होते हैं।

त्वचा की स्थिति: छिलका चिकना और झुरिज़्यों, दरारों, दाग-धब्बों या काले धब्बों से मुक्त होना चाहिए, जो ताज़गी और उचित हैंडलिंग का संकेत देता है।

वजन: एक अच्छा आम अपने आकार के हिसाब से भारी लगता है, जो रसीलापन और गूदे के घनत्व को दशातज़ है।

2. बनावट: दृढ़ता: जब धीरे से दबाया जाता है, तो एक पका हुआ आम थोड़ा सा दबना चाहिए, लेकिन बहुत नरम या गूदा नहीं होना चाहिए। बहुत जूयादा सख्त आम कच्चे हो सकते हैं, जबकि बहुत जूयादा नरम आम जूयादा पके हो सकते हैं।

गूदा: किस्म के आधार पर गूदा चिकना और रसीला होना चाहिए जिसमें कम से कम फाइबर हो। अल्फांसो जैसी प्रीमियम किस्में अपने मक्खनी, फाइबर रहित गूदे के लिए जानी जाती हैं।

3. सुगंध: खुशबू: एक पका हुआ आम एक मीठी, फ्ल जैसी सुगंध देता है, खासकर तने के सिरे पर। सुगंध सुखद और फल के खाने के लिए तैयार होने का संकेत होनी चाहिए।

आम के फलों की जैव रासायनिक विशेषताएं: मिठास की मात्रा: ब्रिक्स स्तर: आम की मिठास को ब्रिक्स डिग्री में मापा जाता है, जो मिठास की मात्रा को दशातज़ है। उच्च गुणवत्ता वाले आमों में आमतौर पर 14-22 का ब्रिक्स स्तर होता है, जो उच्च चीनी सांद्रता और मिठास को दशातज़ है।इस वषज़ जो आम बाज़ार मे उपलब्ध है उसमे आमतौर मिठास पर 10-18 का ब्रिक्स स्तर है।

2. अम्लता: पीएच स्तर: आमों में अम्लता उनके समग्र स्वाद प्रोफ़ाइल में योगदान देती है, जो थोड़ी सी खटास के साथ मिठास को संतुलित करती है। पके आमों का पीएच मान आमतौर पर किस्म के आधार पर 3.4 से 4.8 के बीच होता है।

3. पोषक तत्व: विटामिन: आम विटामिनों से भरपूर होते हैं, खास तौर पर विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड) और विटामिन ए (बीटा-कैरोटीन के रूप में)। उच्च गुणवत्ता वाले आमों में इन विटामिनों का उच्च स्तर बना रहता है, जो उनके पोषण मूल्य में योगदान देता है।

खनिज: इनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे आवश्यक खनिज होते हैं।

अधिक नमी से आम और लीची की फसल को हो रहे हैं भारी नुकसान, जानें सूख रहे पेड़ों को कैसे करें प्रबंधित?

विगत वर्षों में अत्यधिक बारिश होने की वजह से लंबे समय तक बाग में पानी लगे होने की वजह से अब पेड़ के मुख्य तने के छिलके सड़ रहे हैं।

4. फाइटोकेमिकल्स: कैरोटीनॉयड: बीटा-कैरोटीन सहित ये रंगद्रव्य आम के जीवंत रंग में योगदान करते हैं और महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट होते हैं।

पॉलीफेनोल: आमों में मैंगिफेरिन जैसे विभिन्न पॉलीफेनोल होते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और ये फल के स्वास्थ्य लाभों में योगदान करते हैं।

वाष्पशील यौगिक: एस्टर, एल्डिहाइड और टेरपेन सहित ये यौगिक आम की विशिष्ट सुगंध और स्वाद प्रोफ़ाइल के लिए ज़िम्मेदार होते हैं।

5. फाइबर सामग्री: आहार फाइबर: आम आहार फाइबर प्रदान करते हैं, जो पाचन में सहायता करता है। मांस की बनावट फाइबर सामग्री का संकेत दे सकती है, कुछ किस्मों में चिकना, कम रेशेदार मांस होता है।

धीमी हो रही पृथ्वी के आंतरिक कोर के घूमने की रफ्तार

एक नई रिसर्च से पता चला है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर के घूमने की रफ्तार उसकी सतह की तुलना में धीमी पड़ रही है। रिसर्च में इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिले है कि आंतरिक कोर की रफ्तार 2010 के आसपास कम होनी शुरू हो गई थी। ऐसे में आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आंतरिक कोर के घूमने की रफ्तार में होने वाला बदलाव इंसानों को कैसे प्रभावित करेगा। बता दें कि वैज्ञानिकों ने अंदेशा जताया है कि इसकी वजह से आने वाले समय में दिन की अवधि पर असर पड़ सकता है। हालांकि साथ ही उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि दिन के समय पर पड़ने वाला यह प्रभाव एक सेकंड से भी कम होगा।

मतलब साफ है यह बदलाव आम लोगों द्वारा महसूस नहीं किया जाएगा। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए इस अध्ययन के नतीजे 12 जून 2024 को जनज़्ल नेचर में प्रकाशित हुए हैं।

पृथ्वी की संरचना में नजर डालें तो यह मुख्य रूप से तीन परतों में बनी है, जिसकी सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी का यह वो हिस्सा है जिसपर हम इंसान और जैवविविधता बसती है। इसके बाद मेंटल है और तीसरी एवं सबसे अंदरूनी परत को कोर कहा जाता है। यह कोर दो हिस्सों आंतरिक और बाह्य में बंटा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पृथ्वी का यह आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना एक ठोस गोला है, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपने स्थान पर स्थिर बना रहता है। यदि इसके आकार की बात करें तो यह करीब-करीब चंद्रमा के बराबर है। इसकी गहराई के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पृथ्वी की ऊपरी सतह से करीब 4,828 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे स्थित है। चूंकि इतनी गहराई में होने की वजह से सीधे तौर पर इसे देखा या उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। ऐसे में वैज्ञानिक इसके अध्ययन के लिए भूकंपीय तरंगों की मदद लेते हैं।

देखा जाए तो वैज्ञानिकों के बीच इस आंतरिक कोर की गति को लेकर पिछले दो दशकों से बहस चल रही है। कुछ शोधों का मानना है कि यह आंतरिक कोर पृथ्वी की सतह से भी ज्यादा तेजी से घूमता है। लेकिन अपने इस नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि 2010 के आसपास इसकी गति धीमी होनी शुरू हो गई और यह पृथ्वी की सतह से धीमी रफ्तार में घूम रहा है।

इस बारे में अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता प्रोफेसर जॉन विडेल ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि, जब मैंने पहली बार इस बदलाव को दर्शाने वाले सीस्मोग्राम देखे, तो मैं हैरान रह गया। लेकिन इसी पैटर्न का संकेत देने वाले दो दर्जन से अधिक अवलोकन मिलने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि दशकों में पहली बार आंतरिक कोर धीमा हो गया है।

बदलाव के कारण: शोध के मुताबिक आंतरिक कोर अब पृथ्वी की सतह की तुलना में धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, जैसे की यह पीछे की ओर जा रहा हो। ऐसा करीब 40 वर्षों में पहली बार हुआ है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बार-बार आने वाले भूकंपों और भूकम्पीय तरंगों का उपयोग किया है। यह भूकंप एक ही स्थान पर बार-बार आते हैं और समान सीस्मोग्राम बनाते हैं।

अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 1991 से 2023 के बीच दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह के पास 121 बार आने वाले भूकंपों के भूकंपीय आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इसके साथ ही उन्होंने 1971 और 1974 के बीच सोवियत परमाणु परीक्षणों और आंतरिक कोर के अन्य अध्ययनों से दोहराए गए फ्रांसीसी और अमेरिकी परमाणु परीक्षणों के आंकड़ों का भी मदद ली है। विडेल ने इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए प्रेस से साझा की जानकारी में कहा है कि आंतरिक कोर की धीमी होती गति, उसके चारों और बाहरी कोर में घूमते तरल लोहे के मंथन की वजह से है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। इसके ऊपर चट्टानी मेंटल के घने क्षेत्रों से गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है। विडेल के मुताबिक कोर की धीमी होती गति के लिए उसके चारों ओर घूमते तरल लोहा की वजह से है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। इसके साथ ही गुरुत्वाकषज़्ण खिंचाव की भी इसमें भूमिका है। इसके प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए शोधकर्ताओं ने जानकारी दी है कि आंतरिक कोर की गति में परिवर्तन से दिन की अवधि पर मामूली प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन आम लोगों द्वारा इसे नोटिस करना बहुत कठिन है। भविष्य में वैज्ञानिक आंतरिक कोर का अधिक बारीकी से अध्ययन करना चाहते हैं ताकि यह समझा जा सके कि इसमें यह बदलाव क्यों आ रहे हैं। विडेल को लगता है कि आंतरिक कोर की हलचलें हमारी कल्पना से कहीं अधिक दिलचस्प हो सकती हैं।

गौरतलब है कि इसी साल माचज़ 2024 में जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में सामने आया था कि ध्रुवों पर जमा बर्फके तेजी से पिघलने के कारण पृथ्वी की घूर्णन की रफ्तार धीमी हो रही है। इसकी वजह से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी वजह से हमे कुछ वर्षों के भीतर पहली बार लीप सेकंड को घटाने की आवश्यकता पड़ सकती है।

लुप्त होने के कगार पर पहुंची पक्षियों की 144 नई प्रजातियां

वैज्ञानिकों की एक टीम ने कॉर्नेल लैब ऑफऑर्निथोलॉजी में मैकाले लाइब्रेरी की मदद से उन पक्षियों की पहली बड़ी सूची जारी की है, जिन्हें एक दशक से भी अधिक समय से देखा नहीं गया है।

शोध के मुताबिक, मैकाले लाइब्रेरी पक्षी मीडिया का सबसे समृद्ध भंडार है और इसकी मदद से दुनिया के अधिकांश पक्षियों के बारे में दस्तावेज हासिल किए जा सकते हैं।

शोधकर्ताओं ने शोध के हवाले से बताया कि उन्होंने आई नेचरलिस्ट और क्सेनो-कांटो से आंकड़ों का भी इस्तेमाल किया। शोधकताओज़ के द्वारा ऐसी प्रजातियों की तलाश की जो हाल ही में किसी चित्र, वीडियो या ध्वनि रिकॉर्डिंज़ में बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं हुई हैं। यदि पिछले 10 वषोज़ या उससे अधिक समय में पक्षी का कोई मीडिया नहीं है, तो उस प्रजाति को विज्ञान के लिए गायब माना जाएगा। यह सूची अमेरिकन बर्ड कंज़र्वैंसी में गायब पक्षियों की खोज की ओर से तैयार की गई थी। हर साल या दो साल में इन आंकड़ों को दोहराने से खोज योग्य मीडिया के बिना 10-वर्षीय बेंचमार्क के करीब पहुंचने वाली नई प्रजातियों को पकड़ने में मदद मिलेगी।

शोधकर्ताओं ने 4.2 करोड़ फोटो, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड एकत्र किए हैं, जिनमें से 3.3 करोड़ से ज्यादा अकेले मैकाले लाइब्रेरी से हैं। सभी रिकॉडज़ में से, 144 प्रजातियां, सभी ज्ञात पक्षी प्रजातियों का 1.2 फीसदी, लुप्त होने की कगार पर हैं।

शोध के माध्यम से अन्य लुप्त पक्षियों को फिर से खोजा गया है, जिसमें ब्लैक-नेप्ड तीतर-कबूतर भी शामिल है, जिसे पापुआ न्यू गिनी के एक दूरस्थ द्वीप पर 100 से अधिक वर्षों में दर्ज नहीं किया गया था। वर्तमान में सूची में 126 प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकांश विलुप्त होने के कगार पर हैं।

गायब पक्षियों की वैश्विक सूची फ्रंटियर्स इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट नामक पत्रिका में प्रकाशित की गई है।

शोधकर्ताओं के मुताबिक, सार्वजनिक मीडिया डेटाबेस में प्रजातियों की मौजूदगी या अनुपस्थिति का दस्तावेजीकरण करने के लिए पयाज़्त व्यापक और भरोसेमंद होंगे। एक बार जब अनुपस्थित प्रजातियों की पहचान हो जाती है, तो हम उन्हें खोज सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्हें किसी तरह के संरक्षण की आवश्यकता है या नहीं, यह विधि संभावित संरक्षण और पहचान करने में मदद करती है। अधिकांश दर्ज नहीं की गई प्रजातियां एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के बिखरे हुए द्वीपों पर आधारित हैं। कुछ मामलों में, प्रजातियों को केवल इसलिए लुप्त माना जा सकता है क्योंकि उनका निवास स्थान इतना दूर है कि शुरुआत में दिखने के बाद से कोई भी वापस नहीं आया है। महाद्वीपीय अमेरिका में केवल तीन प्रजातियां लुप्त सूची में शामिल हैं: एस्किमो कर्ल्यू, बैचमैन वार्बलर और आइवरी-बिल्ड वुडपेकर। हवाई से छह देशी प्रजातियां सूची में हैं। शोधकर्ता ने शोध में कहा कितने पक्षी, व्हिम्ब्रेल और कर्ल्यू रिश्तेदार विलुप्त हो गए हैं या उस दिशा में बढ़ रहे हैं।

विमानन, कृषि और एआई जैसे विषयों के अध्यापन की होगी बेहतर व्यवस्थाएं

सीएम बोले-प्रदेश में ड्रोन नीति बनाएगी सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए बनाए गए नियमों के अनुकूल कार्य संचालन पहली प्राथमिकता हो। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी विद्यार्थियों के हित में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में ड्रोन नीति बनाई जायेगी। उन्होंने कहा कि विमानन, कृषि और ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंट (एआई) में रोजगार के बढ़ते अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए अध्यापन की बेहतर व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी 55 जिलों में एक जुलाई से पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ समारोहपूवक्र किया जायेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर प्रबंधन पर सतत ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक अधोसंरचनात्मक विकास के लिए राज्य शासन द्वारा पूणज़ सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय स्थित कक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक में विस्तृत चर्चा कर रहे थे।

पायलट ट्रेनिंग के लिए पाठ्यक्रम उपयोगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट महाविद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का चेहरा बनेंगे। ये महाविद्यालय देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श शिक्षण केन्द्र के रूप में पहचान बनाएं, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के साथ ही अन्य संबंधित विभागों, स्थानीय प्रशासन, विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों को सजग भूमिका निभानी है। उच्च शिक्षा, उद्योग, कृषि और अन्य संबंधित विभागों में ड्रोन के उपयोग और प्रशिक्षण के संबंध में रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। विमानन एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे विषयों में युवाओं की बढ़ती रुचि के मद्देनजर गौरव का विषय है कि देश का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग स्कूल खजुराहो में आरंभ किया गया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि हवाई पटटियां जहां-जहां है, वहां वहां पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, निकटवर्ती विश्वविद्यालय के माध्यम से डिग्री और डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था करें। इस पहल से प्रदेश में रोजगार परक शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।

एक जुलाई से प्रारंभ होंगे पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस

इस वर्ष प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अतंर्गत प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफएक्सीलेन्स स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफएक्सीलेन्स स्थापित करने के लिए चयनित महाविद्यालयों में अतिरिक्त पदों की स्वीकृति भी दी गयी है। इसके साथ ही आवश्यक बजट भी उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक जुलाई से प्रारंभ होने वाले एक्सीलेंस कॉलेज जिले का गौरव होंगे। एक्सीलेंस कॉलेज से जिले की तहसीलों एवं जिले के नागरिकों को जोड़ें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रत्येक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र भी खुलेगा। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रमुख निर्देश

- रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करें।
- उच्च शिक्षा विभाग एक्सीलेंस कालेजों में कृषि सहित अन्य उपयोगी पाठ्यक्रम शुरू होंगे। विद्यार्थियों को इसकी व्यवस्थित रूप से जानकारी प्रदान की जाए।
- प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ऐसी छवि निर्मित करें कि अन्य राज्यों के बच्चे यहां पढ़ने आएं, ऐसा वातावरण निमित करें।
- महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में श्रेष्ठ शैक्षणिक कार्यों को पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाए।
- महाविद्यालयों में आवश्यक अधोसंरचना विकास कार्य संपन्न हों। नए पाठ्यक्रम अवश्य प्रारंभ हों। पयटन से सम्बंधित पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ होंगे।
- प्रदेश के उच्च शिक्षा केन्द्र बहु-संकाय सुविधा से युक्त होना चाहिए।
- प्रदेश में अकादमिक सत्र 2024-25 से शुरू हो रहे नवीन पाठ्यक्रम जैसे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स, अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम और अन्य कोर्सेस की जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान की जाए।
- विमानन एवं अन्य पाठ्यक्रमों के लिए की गई व्यवस्थाओं से भी विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाए।
- विद्यार्थियों को महाविद्यालय आने-जाने के लिए परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए।

प्याज इस समय 35 से 40 रुपए के बीच बिक रहा

आलू के बाद लोगों को रुला रही प्याज अचानक कीमत बढ़ने जनता परेशान

गोपालदास बंसल। शहडोल

प्याज के दाम एक बार फिर आसमान छूते नजर आ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में प्याज के दाम 50 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। आने वाले समय में प्याज आपको और रुला सकती है। आलू की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम आदमी पहले से ही परेशान है और अब प्याज की कीमतों में भी आग लग चुकी है। जितनी तेजी के साथ प्याज के दाम बढ़ रहे हैं उससे अभी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो अभी इतनी जल्दी प्याज के दाम में राहत भी नहीं मिलने वाली है। बीते एक हफ्ते में 50 फीसदी से भी ज्यादा दाम प्याज के बढ़ चुके हैं।

प्याज खरीदने सब्जी मंडी पहुंची निशू तिवारी और उनकी मां पार्वती तिवारी बताती हैं कि वो जब भी बाजार आते हैं हर बार 05 किलो प्याज खरीद कर लेकर जाते हैं, लेकिन जिस तरह से प्याज के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इससे उम्मीद कम ही है कि आने वाले समय में प्याज के दाम में कमी आएगी। इसलिए उन्होंने इस बार 01 किलो प्याज ही खरीदा है, गौरतलब है कि 15 से 20 रुपए किलो बिकने वाला प्याज इस समय 35 से 40 रुपए के बीच बिक रहा है।

प्याज के दाम बढ़ने की ये है वजह - आखिर प्याज के दाम इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ रहे हैं। इसे समझने के लिए हमने कई आलू प्याज के व्यापारियों से बात की, वो बताते हैं कि प्याज के दाम के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है कि बेमौसम बारिश और जिस तरह से प्रचंड गर्मी हुई है, उसकी वजह से फसल खराब हुई है। इसके अलावा इस समय प्याज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है जिसकी वजह से भी प्याज के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

तेजी से बढ़ रहे प्याज के दाम

व्यापारी उपेंद्र कुशवाहा पिछले कई सालों से सिर्फ आलू, प्याज और लहसुन ही बेचते हैं। इसी के व्यापार से वह अपना घर चलाते हैं। वो बताते हैं कि मौजूदा साल में प्याज के दाम में जून महीने में ही जिस तरह का इजाफा देखने को मिल रहा है, आने वाले समय के लिए सही संकेत नहीं हैं। प्याज व्यापारी अभिषेक गुप्ता बताते हैं कि वर्तमान में प्याज की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 01 किलो प्याज खरीदने के लिए लोगों को कम से कम 40 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं।

प्याज निर्यात से हटा प्रतिबंध

जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने 06 देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका को 99,150 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी। इसके बाद 04 मई को घोषणा की गई कि भारत ने 2024 में मजबूत खरीफ फसल उत्पादन और अनुकूल मानसून पूर्वानुमानों के साथ-साथ थोक बाजार और खुदरा दोनों स्तरों पर स्थिर बाजार स्थितियों के कारण 07 मई से 06 देशों से प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है।

जून में आती है प्याज

आलू प्याज का व्यापार करने वाले कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि जून महीने से मंडियों में आने वाली प्याज किसान और व्यापारियों के पास मौजूद स्टॉक से आती है, लेकिन किसान अब स्टॉक बेचने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि 2023-24 की रवि फसल में गिरावट आने पर आने वाले समय में कीमत और बढ़ेगी, व्यापारी भी लगातार स्टॉक जमा कर रहे हैं, इससे भी प्याज के भाव बढ़ रहे हैं।

अभी और बढ़ेंगे प्याज के दाम

एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्याज की कीमत इस बार घटने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी, और ये आपको और रुलाएगी। महंगाई में पहले से ही आग लगी हुई है। आलू की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। हरी सब्जियों की कीमतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब प्याज भी लोगों की थाली से गायब हो रहा है। जिस प्याज को स्वाद बढ़ाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं वही प्याज अब लोगों को रुलाने पर मजबूर कर रहा है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की साप्ताहिक समीक्षा की

पंचायतों को स्वावलंबी बनाना ही विभाग का मुख्य टारगेट

भोपाल। जागत गांव हमार

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअली विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव, संचालक पंचायत राज मनोज पुष्प, आयुक्त मनरेगा कृष्ण चैतन्य सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए गए वृक्षारोपण एवं जीर्णोद्धार कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलों में रोपे गए पौधों का शत-प्रतिशत सर्वाइवल रेट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल में भी यह अभियान निरंतर रूप से चलना चाहिए, जिससे खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में संरक्षित रह सके। सभी ज़िले अपनी सीमा में स्थित नदियों के उद्गम स्थल का विशेष ध्यान दें।

रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग पर जोर

मंत्री ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी शासकीय भवनों में रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग की समुचित व्यवस्था की जाए जिससे वर्षा का जल जमीन में उतारा जाकर संरक्षित किया जा सके। नगरीय क्षेत्र की पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाली ग्राम पंचायत तथा नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे पर स्थित बड़ी ग्राम पंचायतों को भी सुनियोजित विकास के दृष्टिकोण के साथ विकसित करना होगा। इस पर भी कार्य नीति तैयार की जाए। मंत्री पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सशक्तीकरण करने के लिये विभाग को इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। रूरल टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। हमें पर्यटन केंद्रों के समीप ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा। मंत्री ने मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

57 व्यापारियों पर एफआईआरः खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर अफसरों ने चलाया अभियान

किसानों के साथ नाप-तौल में धोखाधड़ी करने वालों को बख्शेंगे नहीं

भोपाल। जागत गांव हमार

राज्य सरकार किसानों के साथ नाप-तौल में धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों को चिन्हांकित कर कड़ी कार्रवाई कर रही है। गड़बड़ी करने वाले 57 व्यापारियों को चिन्हांकित कर उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किएगए हैं। नियंत्रक नाप-तौल डॉ. कैलाश बुंदेला ने बताया है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देशानुसार अपर मुख्य सचिव, स्मिता भारद्वाज के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाकर उपकरणों की जांच की जा रही है। बुंदेला ने बताया कि आगामी खरीफ फसल को दृष्टिगत रखते हुए विशेष जांच अभियान चलाकर जिलों में खाद-बीज विक्रेताओं की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। किसानों को सही मात्रा एवं दाम में खाद

एवं बीज बेचने में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं, जिससे कि किसानों को सही कीमत पर उचित मात्रा में कृषि आदान प्राप्त हों। अभियान में विशेष तौर से जांचा-परखा जा रहा है कि व्यापारी द्वारा उपयोग में लाए जा रहे नाप-तौल उपकरण नियमानुसार सत्यापित एवं सही है कि नहीं, खाद एवं बीज के पैकेजों पर नियमानुसार आवश्यक घोषणाए अंकित है कि नहीं। पैकेजों पर अंकित मात्रा के अनुसार खाद एवं बीज है, या नहीं। व्यापारी खाद्य बीज के पैकेजों पर अंकित एमआरपी से अधिक कीमत पर विक्रय तो नहीं कर रहा है। नियंत्रक नाप-तौल डॉ. बुंदेला ने बताया कि विशेष जांच अभियान में खाद एवं बीज व्यापारियों के कुल 324 निरीक्षण में 19 प्रकरण नाप-तौल उपकरण सत्यापित नहीं पाए जाने के कारण, 29 प्रकरण खाद्य एवं वीज के पैकेजो पर नियमानुसार घोषणा अंकित नहीं होने के कारण तथा 09 प्रकरण नाप-तौल उपकरण के सत्यापन प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण पंजीबद्ध किए गए।

सही मात्रा में सही कृषि आदान उपलब्ध कराएं

खाद एवं बीज व्यापारियों को कहा गया है कि वे सत्यापित नाप-तौल उपकरणों का ही उपयोग करे, खाद एवं बीज के पैकेजों पर नियमानुसार आवश्यक घोषणाए अंकित होने पर ही विक्रय के लिये रखें, पैकेजों पर अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर विक्रय न करें। यह सुनिश्चित करें कि किसानों को खाद एवं बीज सही मात्रा में ही मिले। किसी भी व्यापारी के यहां अनियमितता पाई जाने पर नाप-तौल अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बेखौफ होकर व्हाट्स-अप करें

डॉ. बुंदेला ने किसानों से आग्रह किया है कि वे कृषि दुकानों पर खरीदी पर संदेह की स्थिति में बेखौफ होकर जानकारी उपलब्ध करायें, जिससे कि व्यापारियों द्वारा किसानों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं बीज विक्रेता के यहां नाप-तौल, अधिक कीमत लेने संबंधी किसी प्रकार भी अनियमितता पर शिकायत विभाग के व्हाटस-एप नम्बर 9111322204 पर जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में परियोजना पर चर्चा कर दिए निर्देश

किसानों के हित में खरीफ-2024 से लागू करें डिजिटल क्रॉप सर्वे परियोजना

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खरीफ-2024 से कृषक हित में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जाए। इस परियोजना में किसान बंधु नवीन तकनीक से अपनी गिरदावरी को देख सकेंगे। यही नहीं फसल नुकसान की दशा में किसानों को बीमा राशि भी अविलंब प्राप्त हो जाएगी। परियोजना में सैटेलाइट इमेज द्वारा संभावित फसल की जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी। इससे किसानों को उपार्जन में सहायता मिलेगी साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड भी तत्काल स्वीकृत करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास में हुई एक बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना के संबंध में चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा एवं प्रमुख सचिव राजस्व निकुंज श्रीवास्तव से परियोजना के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने परियोजना की सराहना करते हुए इसके क्रियान्वयन से जुड़ी प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए।

डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना

डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना द्वारा ग्राम में उपलब्धि स्थानीय युवा के माध्यम से नवीन तकनीक (जियो फेंस) का उपयोग कर कराया जाएगा। खेत में जाकर फसल का फोटो खींचने की प्रक्रिया आसानी से पूर्ण हो जाएगी। सर्वेयर द्वारा खींची गयी फोटो की जियो टैगिंग भी होगी। अतः अनिवार्य रूप से खेत में जाकर क्रॉप सर्वे करना होगा और साक्ष्य के रूप में फसल की फ़ोटो भी उपलब्ध रहेगी। इससे किसान भी अपनी गिरदावरी को देख सकेंगे और आपत्ति भी दर्ज कर सकेंगे। इस प्रकार नवीन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके साथ ही सैटेलाईट इमेज से भी संभावित फसल की जानकारी प्राप्त कर उसका तुलनात्माक अध्ययगन किया जाएगा एवं विसंगति पाई जाने पर जांच की कार्यवाही शासकीय सेवकों द्वारा की जा सकेगी। इस प्रकार फसल की सटीक जानकारी प्राप्त कर फसल के संबंध में बेहतर पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। परियोजना के क्रियान्वयन से प्रदेश के किसानों को उपार्जन कार्य में भी सहायता मिल सकेगी और उन्हें शीघ्र केसीसी स्वीकृत हो सकेंगे। किसानों को फसल नुकुसान की स्थिति में बीमा राशि भी तत्काल मिल सकेगी।

नदियों के उद्गम मानस यात्रा पर मंत्री पटेल बोले

नदियों की धारा को भी अविरल प्रदूषण मुक्त बनाना हमारा दायित्व

भोपाल। जागत गांव हमार

उद्गम मानस यात्रा में मैंने जाना कि प्रकृति ने अपने संसाधनों से हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। समय रहते हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के आनंदित जीवन के लिए इनका संरक्षण, संवर्धन करना होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने यह बात मंडला जिले की गौर नदी तथा डिंडोरी जिले की छोटी महानदी के उद्गम स्थल की यात्रा के दौरान कही है। मंत्री पटेल द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शुरू की गई मानस यात्रा का कारवां अभियान समाप्त होने के बाद भी जारी है। उन्होंने उक्त नदियों के उद्गम स्थल पर पूजन, पौधरोपण व जनसंवाद किया। मंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान जैंसे-जैंसे में नदियों के उद्गम पर जा रहा हूं, मुझे यह अनुभूति हो रही कि हमने ही इन नदियों की उपेक्षा करके जल का भीषण संकट खड़ा किया है।

नदियों की धारा को अविरल, प्रदूषण रहित बनाना संपूर्ण समाज का दायित्व है। यदि हमें प्रकृति को बचाना है तो अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। न केवल हम वृक्ष लगाएं बल्कि वे जीवित रहे यह भी सुनिश्चित करें। इसलिए अभियान समाप्त होने के बाद भी मानस यात्रा समाप्त नहीं हुई। प्रदेश की हर नदी के उद्गम स्थल पहुंच कर उसको जीवित करने का प्रयास सघन रूप से जारी रहेगा।

श्रीअन्न के बीज किसानों को बांटकर अभियान का किया शुभारंभ

डिप्टी सीएम बोले-हर थाली में मिलेट्स को किया जाए शामिल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विश्व योग दिवस के अवसर पर रीवा में श्रीअन्न (मोटे अनाज) संवर्धन अभियान का शुभारम्भ किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मोटे अनाज को अपने खान-पान में शामिल किया जाना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब हमारे देश में मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का को नियमित रूप से भोजन में शामिल किया जाता था, तब लोग कम बीमार पड़ते थे। उन्होंने कहा कि हमारा देश श्रीअन्न का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और बड़ी मात्रा में श्रीअन्न का निर्यात किया जा रहा है। आज फिर मोटे अनाज को अपनाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोटे अनाज के संवर्धन के लिए प्रयासरत हैं। उनका संकल्प है कि भारतीयों की थाली में मिलेट्स जरूर शामिल हों, जिससे हमारे देश के नागरिक स्वस्थ रहे। इस अवसर पर शुक्ल ने श्रीअन्न के बीज के पैकेट किसानों को वितरित किए।

-ग्रीष्म कालीन मूंग उपार्जन लक्ष्य सीमा 40 प्रतिशत तक बढ़ाएं

शिवराज ने की राज्यों के साथ दलहन उत्पादन की समीक्षा बोले-ग्रीष्म मूंग का लक्ष्य सीमा 40 फीसदी तक बढ़ाएं

भोपाल। जागत गांव हमार

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलहन उत्पादन की नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा समीक्षा की। उन्होंने राज्यों को निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त करने के लिए कहा। समीक्षा बैठक में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने मूंग उपार्जन के 25 प्रतिशत लक्ष्य सीमा को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत-संकल्पित होकर कार्य करेंगे। उन्होंने बैठक में शामिल

मध्यप्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, आंध्रप्रदेश, झारखंड और तेलंगाना के कृषि मंत्रियों व अधिकारियों को वर्ष 2024-25 के लिए दलहन उत्पादन के लिये निर्धारित किए गए लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति के लिए समुचित आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मध्यप्रदेश के लिये वर्ष 2024-25 के लिये तूअर का लक्ष्य 4 लाख टन, मूंग 15.50 लाख, उड़द 9 लाख, मसूर 6.95 लाख, चना 37.50 लाख और अन्य दालों का 2.24 लाख टन सहित कुल 76.19 लाख टन दलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश में बीज के लिए 24 हजार क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

आदर्श दलहन गांव विकसित किए जाएंगे

कृषि मंत्री कंषाना ने बैठक में वर्ष 2024-25 विपणन वर्ष में ग्रीष्मकालीन मूंग के कुल उत्पादन की 25 प्रतिशत उपार्जन लक्ष्य सीमा को बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक करने का अनुरोध किया। मंत्री कंषाना ने ओला-पाला से बचाने के लिए जल्दी पकने वाली तूअर की हाइब्रिड किस्म तैयार कराने के लिए संबंधितों को निर्देश देने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के टीकमगढ़, शिवपुरी, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और हरदा जिलों में आदर्श दलहन गांव विकसित किए जाएंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल भी उपस्थित रहे।

एमपी के केले की सप्लाई अरब देशों में | धार का किसान बोला

केला किंग 60 एकड़ में केले की खेती कर रहे

अगले दो महीने में 100 टन फसल निकलेगी, सालाना 47 लाख का प्रॉफिट

धार। जागत गांव हमार

पारंपरिक खेती छोड़ धार जिले की मनावर तहसील के गांव सातत्तलाई के 42 साल का किसान केले की खेती कर रहा है। इस साल 900 टन केले करीब 97 लाख रुपए में बेचे हैं। इसमें 47 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। किसान का अनुमान है कि अगले दो महीने में करीब 100 टन और केला निकलेगा, जिससे करीब 12 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। जागत गांव हमार के इस अंक में हम अपने पाठकों को बता रहे हैं केले की खेती करने वाले गौरव जाट के बारे में। गौरव ने आर्ट्स स्ट्रीम से ग्रेजुएट है। उनके पास 30 एकड़ जमीन है। इसके साथ ही 30 एकड़ भूमि और लीज पर लेकर कुल 60 एकड़ में केले की खेती कर रहे हैं। 20 से 25 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। गौरव जाट को केला किंग के नाम से भी जाना जाता है। इनके पास केले की खेती की जानकारी लेने जिले के साथ-साथ मध्यप्रदेश के दूसरे जिलों से भी किसान आते हैं।

गौरव जाट से ही जानते हैं कैसे हो रही लाखों में आय और कैसे शुरू की खेती

पहले मैं भी पारंपरिक तरीके से गेहूं, चना, कपास और मक्का की खेती करता था, जिसमें लागत के मुकाबले कम बचत होती थी। बारिश और मौसम की मार से नुकसान भी उठाना पड़ता था। फिर मैंने सोचा क्यों ना खेती में ही नया किया जाए। इसी बीच मुझे महाराष्ट्र के जलगांव जाने का मौका मिला। वहां ड्रिप इरिगेशन के साथ टिश्यू कल्चर तकनीक से केला फसल की जानकारी मिली। मनावर लौटने के बाद यहां पहले से केले की खेत कर रहे किसानों से बात की। उन्होंने बताया कि इसमें दूसरे फसलों से अच्छा मुनाफा मिल रहा है। फिर मैं भी अपने 30 बीघा खेत में केले की खेती शुरू की। इसमें मुनाफा होने लगा तो धीरे-धीरे रकबा दिया। अब मैं 60 बीघा में केले की खेती कर रहा हूं। पिछले साल अप्रैल में 30 बीघा में 24 हजार केले के पौधे लगाए थे। महाराष्ट्र के जलगांव लैब से पौधे मंगवाए थे। अभी तक इसमें से करीब 9 सौ टन केला बेच चुका हूं। जिसमें करीब 47 लाख रुपए का इनकम हुआ है। अभी लगभग 100 टन और केला निकलेगा। जिसमें 12 लाख तक मुनाफा हो सकता है। इसमें मुझे करीब 50 लाख रुपए की लागत आई थी। मेरे केले मध्यप्रदेश के बाहर बिकते हैं। रायपुर, दिल्ली, मुंबई के साथ खाड़ी देश इराक, ईरान और दुबई में सप्लाई हो रहा है। तेज-आंधी तूफान से कुछ पेड़ गिर गए थे। इसके बाद मैंने झाड़ों को आंधी-तूफान से बचाने के लिए बांस का सहारा दिया और फिर से खड़ा किया। 25 मई 2024 को 30 बीघा में करीब 15 हजार पौधे लगाए हैं। 8 से 10 महीने बाद उत्पादन शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर में 8 हजार और नवबंर में 6 हजार केले पौधे लगाऊंगा। इस तरह पूरे साल भर केले का उत्पादन होता रहता है। फसलों के देखभाल के लिए 35 मजदूर खेत पर तैनात रहते हैं। केले के पौधों की कटाई-छंटाई करने के साथ-साथ खराब पत्तों को काटकर अलग करते हैं। जिससे पौधों का विकास नहीं रुकता है।

देश भर में मशहूर है निमाड़ का केला

केले के बेहतर उत्पादन के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त माना जाता है। तापमान में अधिक कमी या वृद्धि होने पर पौधों की वृद्धि, फलों के विकास एवं उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निमाड़ से देश के विभिन्न हिस्सों में केला पहुंचाया जाता है। समय-समय पर इसका निर्यात विदेशों में होता रहा है।

निमाड़ अंचल नर्मदा से जुड़े होने से उत्पादन के लिए बेहतर

मध्यप्रदेश का निमाड़ अंचल नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यहां की जलवायु ना ज्यादा शुष्क है ना ही ज्यादा गर्म। ऐसे में यह इलाका केले के उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है। वहां केले की फसल की क्वालिटी अच्छी होती है। मिट्टी की जांच आप कृषि विभाग से संपर्क कर करवा सकते हैं।

ऐसे करें खेत तैयार

पौधे लगाने से पहले सबसे जरूरी होता है खेत तैयार करना। जहां केले के पौधे लगा रहे हैं। वहां सबसे पहले सफाई कर लें। कम से कम एक महीने पहले खेतों की जुताई हो जानी चाहिए। तीन से चार तिरछी जुताई के बाद पाटा लगाकर मिट्टी को समतल कर लें। आखिरी जुताई के समय गोबर की खाद डालने से फसल और अधिक निकलती है। केले की फसल लगाने के लिए फरवरी से मार्च का महीना सही माना जाता है। खेत की जुताई के बाद अब गड्ढे बना लें। इसके लिए एक ही पंक्ति में लगभग डेढ़ मीटर की दूरी पर गड्ढों का निर्माण करें। पौधे लगाने से पहले इनमें उर्वरक डाल लें। गड्ढे एक फीट गहरे और चौड़े होने चाहिए। तैयार गड्ढों में खाद डालने के बाद उनकी सिंचाई कर लें।

पौधे लगाने के बाद खाद जरूर डालें

गड्ढे बनाने के करीब एक महीने बाद बोवनी की जानी चाहिए। इसके लिए तैयार गड्ढों में छोटा सा गड्ढा बनाकर बिजाई करें। बीज लगाने के एक महीने बाद फसल में खाद डालना जरूरी होता है। बोवनी के तुरंत बाद पहली सिंचाई की आवश्यकता होती है। सर्दियों में एक सप्ताह के अंतराल में सिंचाई जरूरी होती है। वहीं गर्मी के मौसम में हर चौथे दिन सिंचाई की जानी चाहिए। पत्तियों के अलावा पौधों की बढ़ती ऊंचाई का ध्यान रखना भी जरूरी है। जैसे ही पौधे जमीन से एक से डेढ़ मीटर ऊंचाई हासिल कर लें, तो उन्हें बांस का सहारा देकर खड़ा कर देना चाहिए। जिससे आंधी या तेज हवा से पौधों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। खरपतवार और कीटों से फसल को नुकसान होता है। ऐसे में जब भी खरपतवार दिखे तुरंत गुढ़ाई की जानी चाहिए। इसके अलावा

समय-समय पर दवाइयों का छिड़काव करना जरूरी है। फसल लगाने के 11 से 12 महीने में केले तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जरूरत के अनुसार भी तुड़ाई की जाती है। चिप्स, सब्जी के लिए कच्चे केलों की आवश्यकता होती है। कहीं थोड़े पके तो कहीं अच्छी तरह पके केलों की मांग होती है। यदि लंबी दूरी पर फसल को भेजना है तो लगभग 80 प्रतिशत पक जाने के बाद ही तुड़ाई कर लेनी चाहिए।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, भूमिपूजन के लिए किया अनुरोध

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से मध्यप्रदेश के नौ और यूपी के चार जिलों के किसानों को होगा फायदा

मध्यप्रदेश में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की भी दी जानकारी

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश और उत्तरप्रदेश की केन-बेतवा परियोजना का शिलान्यास जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने पीएम से मुलाकात कर उनसे शिलान्यास करने तारीख देने का अनुरोध किया है। उन्होंने पीएम को प्रोजेक्ट के शिलान्यास करने की तैयारी पूरी होने की जानकारी भी दी। यह परियोजना केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के साथ मध्य प्रदेश और उत्तरप्रदेश सरकार के समन्वय के साथ की जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने पर 103 मेगा वाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न की जा सकेगी।

44 हजार 605 करोड़ की परियोजना

केन-बेतवा परियोजना की लागत 44 हजार 605 करोड़ है। इसमें केंद्र सरकार 90 प्रतिशत राशि देगी। वहीं, राज्य सरकारें 5-5 प्रतिशत राशि देंगी। इस परियोजना के पूरा होने पर मध्य प्रदेश में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। वहीं 41 लाख लोगों को सहज तौर पर पीने का पानी मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश के 2 लाख 52 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और पेय जल की सुविधा भी इससे मिल सकेगी।

सिंचाई और पेयजल के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे

केन-बेतवा परियोजना से मप्र के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, शिवपुरी, दतिया और रायसेनजिले को परियोजना का सीधा लाभ मिलेगा। वहीं, उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा, झांसी और ललितपुर जिलो को फायदा होगा। इस परियोजना के पूरे होने से सिंचाई और पेयजल की सुविधा के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे इलाके में पलायन की समस्या पर रोक लगेगी।

18 साल से इंतजार| दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 221 किमी लंबी केन-बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी। 18 साल बाद अब यह योजना कागजों से जमीन पर उतरने जा रही है। केंद्र ने 2023-24 के बजट में मप्र के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान किया है।

- केन-बेतवा परियोजना भूमि-पूजन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री से भूमिपूजन के लिए समय प्रदान करने का अनुरोध किया। डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के सर्वांगीण विकास व जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुझे विश्वास है कि नई केंद्र सरकार पूर्व की भांति मप्र के विकास और उन्नति के लिए सहयोग देती रहेगी। मैंने प्रदेश में चल रही जन-कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति से भी पीएम को अवगत कराया है।

डॉ. मोहन यादव, सीएम

सरकारी आंकड़ेः मई तक किसानों ने की सबसे ज्यादा खुदकुशी

अमरावती में पांच महीनों में हर दिन एक किसान ने की आत्महत्या

भोपाल/नागपुर। जागत गांव हमार

देशभर के किसान अपनी मांगों को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। कई किसानों ने तो आत्महत्या जैसा कदम भी उठाया है। वहीं किसानों की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र ने यवतमाल को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले कुछ सालों में कपास उत्पादक यवतमाल जिला महाराष्ट्र में नंबर वन पर जाना जाता रहा है। अब यवतमाल की जगह अमरावती जिले ने ले ली है। महाराष्ट्र के अमरावती में किसानों की आत्महत्या करने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। यहां जो आंकड़े सामने आए हैं वह डरावने हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या अमरावती टॉप पर है। यवतमाल की सीमा से लगा अमरावती कपास और सोयाबीन का उत्पादक क्षेत्र है। प्रसिद्ध नागपुर संतरे की खेती भी यहीं होती है। इस साल मई 2024 तक अमरावती में 143 किसानों ने आत्महत्या की है। यह आंकड़े महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पांच महीनों में करीब हर दिन एक किसान ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के मामले में दूसरे नंबर पर यवतमाल है। हालांकि दोनों जिलों में किसानों की आंत्महत्या के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मई 2024 तक 132 आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं। जून के आंकड़े अभी संकलित किए जाने बाकी हैं। अमरावती ने 2021 से आत्महत्या के मामले में यवतमाल को पीछे छोड़ दिया है। 2021 में यवतमानल में 370 किसानों ने आत्महत्या की थी। 2022 में 349 और 2023 में 323 किसानों ने आत्महत्या की। यवतमाल में 2021 से 2023 तक यह संख्या 290, 291 और 302 तक थी। महाराष्ट्र सरकार की टास्क फोर्स के वसंतराव नाइक शेतकरी स्वावलंबन मिशन के पूर्व अध्यक्ष किशोर तिवारी ने इस पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अमरावती में स्थिति विशेष रूप से कठिन है।

132 आत्महत्याओं में से 34 में कृषि संकट कारण

किसानों ने सोयाबीन की खेती की और उपज में उल्लेखनीय गिरावट देखी। पिछले साल दरें गिरकर चार हजार रुपए प्रति क्विंटल हो गईं। बैंकिंग ऋण की कमी के चलते लोग छोटी वित्त कंपनियों या साहूकारों पर निर्भर हैं और उन्हें कठोर वसूली का सामना करना पड़ता है। 2001 से राज्य सरकार विदर्भ के छह जिलों अमरावती, अकोला, यवतमाल, वाशिम, बुलढाणा और वर्धा में किसानों की आत्महत्याओं का डेटा रख रही है। दो दशकों में इन जिलों में 22,000 से ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। आत्महत्याओं को उन किसानों के बीच विभाजित किया जाता है जो राज्य सरकार से एक लाख रुपए के मुआवजे के पात्र हैं और जो नहीं हैं। जिला स्तरीय समिति यह जांच करती है कि आत्महत्या कृषि संकट या अन्य कारणों से हुई है या नहीं। मुआवजे के लिए पात्र होने के लिए, पीड़ित को ऋण, वसूली दबाव, फसल की विफलता और खेती से संबंधित अन्य संकटों का सामना करना पड़ा होगा। अमरावती में मई तक दर्ज 143 आत्महत्याओं में से 33 में कृषि संकट का मामला दर्ज है। दस मामले खारिज कर दिए गए हैं और 100 की जांच चल रही है। यवतमाल में मई तक 132 आत्महत्याओं में से 34 में कृषि संकट को आधिकारिक कारण बताया गया है। 66 मामलों की जांच चल रही है और जिला प्रशासन ने 32 को खारिज कर दिया है।

दमोह में बिना मां बने रोजाना 14 लीटर दूध दे रही गाय, डॉक्टर-वैज्ञानिक बोले दुर्लभ

दमोह। जागत गांव हमार

क्या आपने कभी सुना है कि कोई गाय बिना बछड़े को जन्म दिए दूध दे रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा हो रहा है। दरअसल मधयप्रदेश के दमोह जिले से ये अजीब गजीब मामला सामने आया है। जहां एक गाय में किसान के पास ऐसी गाय है जो एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे तीन महीने से बिना मां बने ही दूध दे रही है। दूध भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि रोजाना का 14 लीटर है। इस गाय के बारे में जब वेटरनरी डॉक्टर को बताया गया तो वो भी हैरान रह गए।

चौंका देने वाला ये मामला दमोह के बटियागढ़ ब्लॉक के मुहली गांव का है। गांव में रहने वाले किसान देवेन्द्र लोधी के पास एक ऐसी गाय है जो बीते तीन महीनों से बिना बछड़े को जन्म दिए दूध दे रही है। किसान देवेन्द्र लोधी का कहना है कि उन्होंने इस जर्सी नस्ल की गाय को जबलपुर से खरीदा था। गाय की बच्चा दानी में गांठ थी जिसका इलाज कराया और दवा देने के एक हफ्ते बाद गाय के थनों में दूध आने लगा। अब यह गाय दिन में कुल 14 लीटर तक दूध देती है। शुरूआत में ऐसा हुआ तो वो भी हैरान रह गए। देवेन्द्र लोधी के मुताबिक जिसको भी उन्होंने इसके बारे में बताया उसने विश्वास नहीं किया। वेटरनरी डॉक्टर को जब बिना मां बने गाय के दूध देने की बात बताई तो वो भी हैरान रह गए।

वेटरनरी डॉक्टर ने कहा अनोखा मामला

बिना मां बने गाय के इस तरह से दूध देने को लेकर पशु चिकित्सकों का कहना है कि गाय के हार्मोनल बदलाव के कारण दूध आना शुरू हो गया है। लेकिन ये दुर्लभ मामला है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि हार्मोनल बदलावों के चलते ऐसा होना संभव है, लेकिन यह बहुत कम ही देखने को मिलता है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)